www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 317 || लखनऊ
शनिवार
21 फ़रवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:38
सूर्यास्तः 06:02
अधिकतमः 28°00
न्यूनतमः 15°00

पेज 03

विशेष समाचार
- मोहन भागवत के बयान पर इतना... >> पेज 02
- बिजलीकर्मियों का थाने पर प्रदर्शन... >>पेज 04
- बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ...

मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए, बीजेपी बोली- राहुल के घर पर प्लानिंग हुई

एआई समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा

प्रदर्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को AI समिट 2026 में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड' के नारे लगाए। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें 15-20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी-शर्ट लिए हुए हैं। टी-शर्ट पर PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की फोटो लगी है। उसपर लिखा है- PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी कृष्णा हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइस प्रसिडेंट अजय कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की है। BJP सांसद संबित पात्रा ने कहा- यह संयोग नहीं, बल्कि एक प्रयोग था। इसकी प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर बनाई गई थी, जहां सोनिया और प्रियंका मौजूद थीं। भाजपा ने AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने X पर पोस्ट में लिखा- यह कांग्रेस के अहंकार और हताशा का प्रदर्शन है! राहुल गांधी के लिए भारत को अपमानित करना ही सरकार को निशाना बनाने का तरीका है। जो बाजार में 2-3 लाख रुपए में उपलब्ध है। वहीं ड्रोन 40 हजार वाला रेडीमेड 'स्ट्राइककर V3 ARF' मॉडल था। विवाद के बाद सरकार ने यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर निकाल दिया था।

एआई समिट में प्रदर्शन पर नेताओं की प्रतिक्रिया

तरुण चुघ, भाजपा नेता - 'कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की है। ये साजिश के तहत की गई है। जो माफ नहीं की जा सकती है। देश की जनता इस तरह के हरकतों के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।'

मनोज झा, RJD सांसद - 'मेरा मानना है कि देश में आक्रोश है और यह आक्रोश कई मोर्चों पर है लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के समिट में विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं था।'

उदय भानु चिब, इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष- हमारे युवा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी के सिपाही हैं। वे डरेंगे नहीं। जब राहुल गांधी के खिलाफ FIR नहीं थी, तब भी ED का मामला इतने सालों तक चलता रहा। भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन हम संविधान के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे।'

पुलिस बोली- प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था

दिल्ली पुलिस में एडिशन कांस्टेबल देवेश कुमार महला ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे घटी। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और क्यूआर कोड स्कैन करके समिट हॉल में एंट्री की। उन्होंने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर टी-शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और टी-शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं पर पुलिस के साथ झड़प करने का भी आरोप है।

पीएम ने 16 फरवरी को एआई समिट का उद्घाटन किया था

2026 इंडिया AI इंपैक्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। यह 20 फरवरी तक होना था लेकिन भीड़ और आयोजनों के चलते इसे 21 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को समिट का उद्घाटन किया था। यहां दुनियाभर की कंपनियों ने अपने लेटेस्ट AI सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया है। यहां आम लोग देख सकते हैं कि AI असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में AI से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है।

राहुल के घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया

AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'राहुल गांधी मुर्दाबाद' और 'राहुल गांधी हाय-हाय' के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के पोस्टर भी जलाए। काफी हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।

> दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले काले रंग के छाते पर स्टिकर चिपकाकर भारत मंडपम में घुसने की योजना बनाई थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गेट पर जांच के दौरान काले छाते पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने टी-शर्ट पर स्टिकर चिपका दिए। स्टिकर कहां छपवाए गए थे, यह पता लगाने के लिए जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गिरफ्तार किए गए चार कार्यकर्ताओं को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण विवादों में आया एआई समिट

AI समिट उद्घाटन के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहा। विवाद तब और बढ़ा जब उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने समिट के दौरान अपने स्टॉल पर रोबोटिक डॉग 'ओरायन' प्रदर्शित किया था। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने चीन में बने रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताकर समिट में दिखाया। चीनी रोबो डॉग के साथ ही यूनिवर्सिटी ने कोरियन कंपनी के एक ड्रोन को भी अपना बताया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कई टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि रोबोट डॉग चीनी कंपनी 'यूनिट्री' का 'Go2' मॉडल है।

समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल

इस समिट की थीम राष्ट्रीय विजन 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', यानी सभी का कल्याण, सभी का सुख पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानवता के लिए AI के वैश्विक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसके अलावा लगभग 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 60 से ज्यादा मंत्री, और 45 से ऊपर तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए। इसके अलावा 300+ प्रदर्शक और 30+ देशों की थीम पवेलियन्स भी समिट का हिस्सा रहे हैं, जो वैश्विक साझेदारी और AI के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

> राजनीति होती है, आरोप-प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ सौदेबाजी असहनीय है। कांग्रेस के युवा विंग ने एआई समिट में अराजकता फैलाने की कोशिश की। भारत की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की कोशिश शर्मनाक है।
>
> योगी आदित्यनाथ
> मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

बंगाल सरकार और ईसी में भरोसे की कमी : सुप्रीम कोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश- एसआईआर प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारी तैनात करें

निर्देश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच जारी विवाद पर 'असाधारण' निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जज को तैनात करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार और आयोग के बीच विश्वास की कमी है। SIR ड्राफ्ट रोल से जुड़े दावे और आपत्तियों का निपटारा और निगरानी हाईकोर्ट की ओर से अपॉइंट अफसर और जज करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के आदेश अदालत के आदेश माने जाएंगे। कलेक्टर और एसपी को इन आदेशों का पालन कराना होगा। साथ ही चुनाव आयोग को 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की परमिशन दी गई है।

>> (शेष पेज 04 पर)

जाति-मजहब देखना सरकार के लिए पाप : योगी

सपा गरीब ब्राह्मणों को ही स्कॉलरशिप दे देती

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। योगी ने सदन में 2 घंटे 50 मिनट की बजट स्पीच दी। योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। यदि सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा- अरे पांडेय जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया- गरीब ब्राह्मण जीने तो पाएं। सीएम ने कहा, सपा सरकार में हर साल इंसेफेलाइटिस से 1500 से 1700 SC- ST बच्चों की मौतें होती थीं। 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। हमने किसी की जाति नहीं देखी। सपा की 4 बार सरकार बनी, लेकिन आपने विचार तक नहीं किया। दरअसल, AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर चीन में बना एक रोबोट प्रदर्शित किया था और दावा किया था कि इसे उनके छात्रों ने तैयार किया है। पोल खुलने के बाद सरकार ने यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया था।

फास्ट न्यूज

जबलपुर के पास आरती-अजान के विवाद में बवाल

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से करीब 40 किमी दूर सिहोरा तहसील में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर और मस्जिद के बीच आरती-अजान को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है।

महिला के पेट से कैंची नुमा सर्जिकल टूल निकला

अलाप्पुझा। सर्जरी के 5 साल बाद महिला के पेट में सर्जिकल टूल (आर्टरी फोर्सेप्स) मिलने का मामला सामने आया है। केरल के अलाप्पुझा के पुन्नप्रा गांव की रहने वाली उषा जोसेफ (51) के पेट में टूल मिला है। ऊषा के बेटे शिबिन ने बताया कि मां की मई 2021 में अलाप्पुजा मेडिकल कॉलेज में गर्भाशय की गांठ की सर्जरी हुई थी। इसके बाद वह घर आ गई थीं, लेकिन उनके पेट में लगातार दर्द बना रहता था। शिबिन के मुताबिक मां का पेट दर्द का इलाज लगातार चल रहा था। हमे लगा कहीं किडनी में स्टोन तो नहीं, इसलिए उनका एक्स-रे कराया। उनके पेट में आर्टरी फोर्सेप्स (छोटी ब्लड वेसल्स को पकड़ने का टूल) नजर आया।

कर्नाटक में मेडिकल स्टूडेंट ने प्रोफेसर को पीटा

बेंगलुरु। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के डॉ. मलाकरेड्डी होम्योपैथिक कॉलेज में एग्जाम के दौरान चीटिंग करने से रोके जाने पर स्टूडेंट ने प्रोफेसर की पिटाई कर दी। घटना इंटरनल एग्जाम के दौरान घटी, जिसका वीडियो क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में दिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिवराजकुमार परीक्षा निरीक्षक के तौर पर छात्रों की निगरानी कर रहे थे।

शाह मानहानि केस : राहुल गांधी का आरोपों से इनकार

कहा- राजनीतिक साजिश में फंसाया, सुल्तानपुर में मोची के परिवार से मिले

- कोर्ट से निकलने के बाद राहुल रामचेत मोची की दुकान पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। यहां करीब 5 मिनट तक रहे।
- कोर्ट से बाहर निकले तो उनसे मिलने और देखने के लिए भारी भीड़ पहुंच गई, ऐसे में सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दूसरे गेट से बाहर निकाला।

तमसा संकेत, एजेंसी

गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार, कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने पर धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको सफाई देनी है? इस पर राहुल ने कहा–हां। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे।

>> (शेष पेज 04 पर)

अब अप्रैल से हर महीने मिलेंगे 18000 रुपये

होली से पहले योगी सरकार का शिक्षामित्रों को तोहफा

घोषणा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को होली पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय लगभग दोगुणा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बजट सत्र के समापन पर विधान सभा सदस्यों को संबोधित करने के दौरान इसकी घोषणा की। अप्रैल माह से शिक्षामित्रों को मानदेय के रुप में प्रतिमाह 18000 रुपये मिलेंगे। इनको अभी तक 10000 रुपया मिलता है। इसी तरह से अनुदेशकों को प्रतिमाह 17000 रुपये मिलेंगे।

>> (शेष पेज 04 पर)

शिक्षामित्रों के मानदेय में कब हुई थी बढ़ोतरी

2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षामित्रों के वेतन में बढ़ोत्तरी हुई थी। उस दौरान शिक्षामित्रों का वेतन तीन हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया था। यूपी में 1.42 लाख शिक्षामित्र और 28 हजार से अधिक अनुदेशक हैं। शिक्षा मित्रों को 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान 2014-15 में शिक्षामित्रों को स्थायी कर दिया था। उस समय शिक्षामित्रों का वेतनमान सहायक अध्यापकों के बराबर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद हो गया था।

सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपये

सरकार ने बालिका छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने को 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.50 लाख से अधिक शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इसके अलावा लगभग 25,000 के आसपास अनुदेशक अलग-अलग परिषदीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। इस फैसले से करीब 1.75 लाख कर्मियों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद हो गया था।

> मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को अप्रैल से 18000 रुपये मानदेय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों से उन्होंने कहा कि आप शिक्षामित्र को 3000 रुपये देते थे। हमने इसको पहले 10000 और अब 18000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय के लिए 580 करोड़ की व्यवस्था की गई और सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ की व्यवस्था है।

सख्ती : असम से ₹6900 करोड़ की योजना लॉन्च की, कहा- 5 साल में राज्य को बाढ़मुक्त करेंगे

कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ीं, घुसपैठ बढ़ी : अमित शाह

> कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी दो दिन के असम दौरे पर है। प्रियंका शुक्रवार सुबह गुवाहाटी के पास सोनापुर पहुंचीं। यहां उन्होंने गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की।

तमसा संकेत, एजेंसी

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने देश की सीमाएं खुली छोड़ दी थीं, जिसकी वजह से असम में घुसपैठ बढ़ी। भाजपा सरकार ने इस समस्या से सख्ती से निपटा है। शाह ने असम के कछार जिले में जनसभा में कहा कि कांग्रेस के शासन में असम में कोई विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। आज राज्य में हर दिन 14 किलोमीटर सड़क बन रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। शाह दो दिन के लिए असम दौरे पर हैं।

सीआरपीएफ के परेड में भी शामिल होंगे

शाह नाथनपुर स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा चौकी का भी निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वे शनिवार को गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में CRPF के वार्षिक दिवस परेड में शामिल होंगे। यह आयोजन पहली बार पूर्वोत्तर में हो रहा है इसके अलावा वे सोनापुर के कसुतोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्य का दौरा किया था।

अमित शाह के भाषण की 5 बड़ी बातें...

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सीमावर्ती गांवों का विकास है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम उसी दिशा में उठाया गया कदम है।
- योजना के दूसरे चरण में 6,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 1,954 गांव इसमें शामिल हैं।
- वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे 334 ब्लॉकों का समग्र विकास किया जाएगा।
- योजना का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकना और अंतर-राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली घुसपैठ पर अंकुश लगाना है।
- पिछले 10 साल में भाजपा ने असम के विकास को नई दिशा दी है। अगले पांच साल में हम असम को बाढ़मुक्त राज्य बनाएंगे। असम पिछले 10 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बना है।

गौरव गोगोई सही रास्ते पर हैं:प्रियंका गांधी

हिमंता चुनाव से डरे, इसलिए आरोप लगा रहे, परिवार को राजनीति में घसीटना गलत

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

गुवाहाटी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि गौरव गोगोई और उनके परिवार को 'पाकिस्तान लिंक' के आरोपों में घसीटना गलत राजनीति है। प्रियंका ने कहा कि असम के सीएम चुनाव से पहले डर गए हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्हें निजी आरोपों की बजाय राज्य के विकास पर बात करनी चाहिए। प्रियंका बोली- गौरव जी और उनके परिवार को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि यह गलत राजनीति है। असम की जनता जानती है कि दूसरी तरफ के लोग उनसे घबराए हुए हैं। वह सही रास्ते पर चल रहे हैं। यह उनके लिए सम्मान की बात है। प्रियंका गांधी का आज असम दौरे का दूसरा दिन है। सुबह वह गुवाहाटी के पास सोनापुर पहुंचीं। गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। प्रियंका गांधी ने हिमंता के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कई कारक तय करते हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

सिविल सेवा परीक्षा में सही सुधार

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस संस्था में समय के अनुसार लगातार सुधार और समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहती है। 2026 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के कुछ कदम स्वागतयोग्य हैं। इनके अनुसार परीक्षा में अंतिम रूप से सफल होने पर यदि किसी उम्मीदवार को ग्रुप ए की कोई सेवा मिल जाती है, तो उसके बाद उसे आइएएस, आइएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए केवल एक अवसर और मिलेगा। उसके बाद परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह अपने विभाग से प्रसन्न नहीं है, तो त्यागपत्र देकर फिर से परीक्षा दे सकता है। आइएएस और आइएफएस में एक बार चुने जाने के बाद फिर से परीक्षा में बैठने की इजाजत पहले की तरह अभी भी नहीं होगी। वैसे यहां लोकतांत्रिक ढंग से एक गुंजाइश छोड़ी गई है। लगभग 23 विभागों में पांच विभाग जैसे अगर दिल्ली में दानिक्स या पुडुचेरी पुलिस आदि में ग्रुप बी की सेवा मिलती है तब जरूर उसे एक से ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। इस एक सुधार से कई स्तरों पर फायदा होगा। सबसे पहले नए उम्मीदवारों के लिए ज्यादा पद खाली मिलेंगे, वरना पहले से सफल उम्मीदवार बार-बार उन्हीं पदों पर चुने जाते रहे हैं। एक बार चुने जाने वालों के लिए भी एक और अवसर देने से वे लगातार 30-35 वर्ष तक परीक्षा में शामिल होने के लोभ से बच जाएंगे। सभी सेवाओं के वेतनमान और सुविधाएं लगभग बराबर ही होती हैं। पहले इन विभागों को उम्मीदवार तो आवंटित हो जाते थे, लेकिन उनमें से कितने ज्वाइन करेंगे, कोई पता नहीं होता था। कुछ फिर से परीक्षा में बैठने के लिए लगातार दो-चार वर्षों तक कई बहाने जैसे मेडिकल, मां की बीमारी आदि बताकर कोशिश करते रहते थे। इससे उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण की समस्याएं पैदा होती थीं। नतीजतन प्रशासनिक क्षमता में लगातार गिरावट आ रही थी। अब सभी विभाग बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इससे सभी विभागों की ट्रेनिंग और क्षमता भी बेहतर होगी। इस सुधार के सामाजिक परिणाम भी अच्छे आएंगे। जब जाति विशेष के कारण किसी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनंत छूट रहती है, तब तक उसके अंदर बार-बार परीक्षा देने की भूख भी कायम रहती है, लेकिन प्रश्न है कि कितने उम्मीदवारों के लिए यह संभव है? क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान पीढ़ी की क्षमता और ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? क्या यह सामाजिक-जातीय विभाजन की तरह सेवाओं में भी कमतर और बेहतर की भावना पैदा नहीं करता? उनके अभिभावक भी लगातार चिंता में डूबे रहते हैं कि उनकी परीक्षा के चक्र कब खत्म होंगे? देश को इन सबसे मुक्ति चाहिए। मौजूदा सुधार का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है और वह है राज्यवार कैडर में उम्मीदवारों का वितरण। नौकरशाही के स्टील फ्रेम में आइएएस सबसे मजबूत आधार होता है। जिस राज्य के लिए उनका आवंटन होता है, वे उस राज्य में ही रहते हैं या फिर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, लेकिन उस राज्य में बने रहने के कुछ दुष्परिणाम अतीत में अनुभव किए गए। जैसे जब पंजाब में आतंकियों ने कहर बरपा रखा था, तब अहसास हुआ कि वहां नियुक्त कुछ अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच मिलीभगत हो गई थी। इसलिए बाद में यह फैसला किया गया कि किसी भी राज्य में वहां के रहने वाले उम्मीदवारों के एक तिहाई से ज्यादा नहीं तैनात होंगे और दो तिहाई उम्मीदवार दूसरे राज्यों के होंगे। देश की एकता में इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। यदि ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य राज्य में तैनात होते हैं, तो भाई-भतीजावाद जैसे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम रहती है। अब इसी में एक कदम और बढ़ाकर इसे और पारदर्शी ढंग से किया गया है। इससे उम्मीदवारों में यह अहसास और पुख्ता होगा कि पूरा देश आपका है और आपको कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती है। हालांकि सरकार नए नियमों को कितनी दृढ़ता से लागू करती है, यह एक सवाल है। पुराने अनुभवों पर नजर डालें तो 1986 में भी इससे कुछ मिलते-जुलते कदम उठाए गए थे। तब परीक्षा देने के प्रयासों पर ऐसी ही रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके खिलाफ दशकों तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई। झूठ-सच के आधार पर उम्मीदवारों ने छुट्टी ली और फिर से वर्षों तक परीक्षाएं दीं। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचा और उसकी कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ा। अफसरों के बीच जो परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, उसके बदले उनमें ईर्ष्या पनपने लगी। जब सभी सेवाओं की लगभग 99 प्रतिशत सुविधाएं बराबर हैं तो इनकम टैक्स में काम करने वाला रेलवे में काम करने वाले को कमतर क्यों समझता है? अपने देश में आइएएस या आइपीएस का नशा तो सातवें आसमान पर रहता है। यह भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि वह जन्म से ही बराबरी नहीं सिखाता। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा भी है कि संविधान में तो हमने बराबरी ला दी, लेकिन समाज अभी उससे बहुत दूर है। इससे देश को नुकसान पहुंच रहा है।

मोहन भागवत के बयान पर इतना बवाल क्यों

> **अगर किसी को हिन्दू से मुस्लिम बनाया जा सकता है तो मुस्लिम से हिन्दू बनाने में क्या परेशानी है। 800 साल राज करने का दावा करने वाले मुस्लिम आज आरक्षण की लाइन में लगे हुए हैं। जिन दलितों-आदिवासियों और पिछड़ों का कई हज़ार तक शोषण-उत्पीड़न किया गया, उनको आरक्षण देना समझ आता है।**

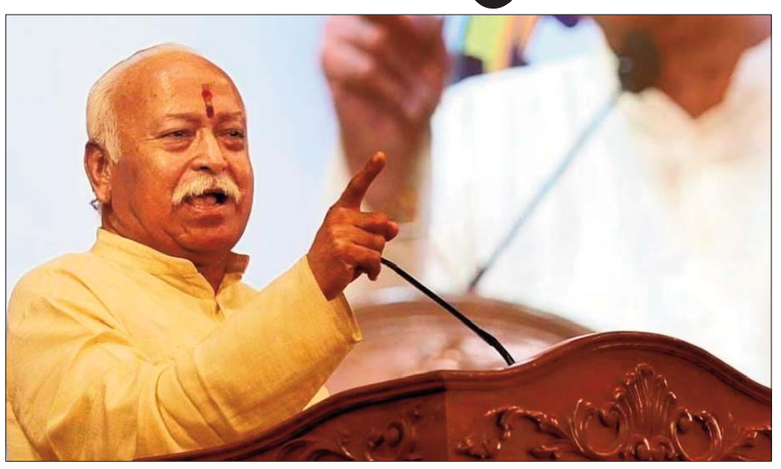

मोहन भागवत के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको लेकर इतना बवाल किया जा रहा है । मंगलवार को मोहन भागवत ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी । उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जड़े भी इसी भूमि से जुड़ी हुई हैं । मुस्लिम यहीं के पूर्वजों की संतान हैं, इसलिए समाज को बांटने की जगह जोड़ने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं, ईसाई हैं लेकिन अरब या तुर्क नहीं हैं और न ही यूरोपियन हैं । हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय हैं । उन्होंने कहा कि ये बात जब उनका नेतृत्व करेगा, तब सब ठीक हो जाएगा । हिन्दू समाज आतुरता के साथ इसकी राह देख रहा है । उन्होंने कहा कि यहां सब हिन्दू हैं. हमें उनकी घरवापसी करवानी है । उन्होंने घरवापसी का जिक्र करते हुए कहा कि यह कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक संवाद और समझ के जरिये धीरे-धीरे होने वाला कार्य है । जनसंख्या के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि हिन्दू समाज में घटती जन्मदर चिंता का विषय है और उनका मानना है कि एक परिवार में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए ताकि संतुलन बना रहे । उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें विवाह के बाद परिवार के विस्तार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । उन्होंने कहा कि समाज में संवाद और सहयोग दोनों ओर से होना चाहिए । उन्होंने जाति व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज को जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर सोचना चाहिए । वर्षों से इसे समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है । उन्होंने कहा कि मुगल और अंग्रेजी शासन की लंबी अवधि के बावजूद भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा मजबूत बनी रही, इसलिए आज भी समाज को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए । उन्होंने किसी किस्म की हिंसा की बात नहीं की और न ही कहा कि देश के सभी मुसलमानों को जबरदस्ती हिन्दू बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ संवाद से किया जाएगा। घरवापसी की बात करना इतना उत्तेजक कैसे हो गया कि देश का पूरा मुस्लिम समुदाय उबल पड़ा, ये समझना मुश्किल हो रहा है। संघ प्रमुख भागवत के बयान की प्रतिक्रिया में जो बयान आएं हैं, बेहद चिंताजनक हैं। मोहन भागवत के बयान पर पूरे देश में घमासान मच गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भागवत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द शुरू से ही ऐसी साम्प्रदायिक और नफरत फैलाने वाली सोच की विरोधी रही है। जब तक यह जिंदा रहेगी, इसका विरोध करती रहेगी । सवाल यह है कि क्या मदनी यह मानने को तैयार हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाना गलत है, ये शबाब का काम नहीं है। मुस्लिम तो मानते हैं कि अगर वो किसी हिन्दू को मुस्लिम बना देते हैं तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करता है। जब धर्मपरिवर्तन की मुहिम में जुटे मुस्लिमों से कहा जाता है कि वो ये काम क्यों करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि उनका धर्म उन्हें ये काम करने के लिए कहता है। घर वापसी तो धर्मपरिवर्तन करके हिन्दू से मुस्लिम बने लोगों को वापस अपने धर्म में लाने का काम है । अगर ये साम्प्रदायिक और नफरत फैलाने वाला काम है तो ये काम तो मुस्लिम पिछले एक हज़ार सालों से करते आ रहे हैं। जब अरबों ने इस देश पर हमला शुरू किया तो इस देश में कोई मुस्लिम नहीं था। अगर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की मुस्लिम आबादी को गिना जाए तो ये संख्या लगभग 80 करोड़ बनती है। क्या मदनी इसे झुठला सकते हैं कि इन सभी लोगों के पूर्वज हिन्दू नहीं थे। भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि अरब इस क्षेत्र के मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं मानते हैं। वो इन्हें कनवर्टेड हिन्दू कहते हैं। जहां इस्लाम पैदा हुआ, वो ये सच जानते हैं लेकिन भारतीय मुस्लिम सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। मदनी ने आगे कहा कि जो 70 साल में कहने वाले पैदा नहीं हुए, वो बातें आज कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुस्लिमों और 6 करोड़ ईसाईयों की घरवापसी की जाएगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है, और किसी ने नहीं पिया है। मदनी ने कहा कि सच यह है कि जो आवाज देश को तबाही, बर्बादी और आपस में दुश्मनी की तरफ ले जाये, वह देश के प्रति वफादारी की आवाज नहीं हो सकती। मदनी ने आगे कहा कि देश में नफरत की आग भड़कायी जा रही है, हिंसा का माहौल बना हुआ है और दिनदिहाड़े लिनचिंग की घटनाएं हो रही हैं। गाय के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों ने मोहन भागवत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी के नेता ने भागवत को कसाब बता दिया है। मदनी ने कहा है कि भागवत के बयान पर सरकार चुप है, इसका मतलब है कि सरकार उनके साथ है। कितनी अजीब बात है कि मोहन भागवत ने जितने शांत मन से अपनी बात रखी, उनका विरोध करने वाले उतने ही उग्र हो रहे हैं। समस्या यह है कि भागवत ने शांति के साथ जो सच कहा है, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इस देश के हैं, वो अरब या तुर्क नहीं हैं। सच यह है कि भारत का मुस्लिम खुद भारतीय से ज्यादा अरब और तुर्क मानता है। पाकिस्तान ने कट्टरता का अंजाम देख लिया है तो वहां ये आवाज उठ रही है कि हम भारतीय हैं, अरब या तुर्क नहीं हैं। भारत में लूटमार और कत्लेआम करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय मुस्लिम अपना हीरो मानते हैं। जिन लोगों ने हिन्दू समाज का भयंकर नरसंहार किया, उन्हें मुस्लिम अपना हीरो मानेंगे, तो भाईचारा कैसे पैदा होगा। जहां इस्लाम पैदा हुआ, वहां ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती है लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की जिद होती है कि वो गाय की कुर्बानी देंगे। वास्तव में यह काम धार्मिक उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है, क्योंकि हिंदू गाय की पूजा करते हैं। इस्लाम के पवित्र त्यौहार को हिंदुओं को अपमानित करने का साधन बनाया जाता है। जिस समुदाय के साथ भाईचारा निभाने की बात कही जा रही है, उसे मौका मिलते ही अपमानित किया जाता है। गाय के नाम पर हत्या की बात कही जा रही है लेकिन गाय हत्या रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। मुस्लिम धर्मगुरु क्यों नहीं कहते कि अगर हिन्दू समुदाय गाय की पूजा करता है तो हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। भारत में इस्लामिक शासन के दौरान समय-समय पर हिन्दू समाज को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया है। उन्हें धर्मपरिवर्तन और मौत में से एक का चुनाव करने के लिए कहा गया और करोड़ों हिंदुओं को मौत चुननी पड़ी। करोड़ों हिंदुओं ने अपनी जान बचाने के लिए धर्मपरिवर्तन कर लिया। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के सामने तीसरा विकल्प जजिया कर का रखा था, जो मुस्लिम नहीं बनते थे, उन्हें जजिया देना पड़ता था। अजीब बात है कि जिन लोगों ने तलवार के डर से या कर से बचने के लिए धर्मपरिवर्तन कर लिया, वो आज सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की मुहिम चला रहे हैं।

राजेश कुमार पासी

जन सुराज का...

ललित गर्ग

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तारः एक सार्थक पुकार

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतर-राष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम "समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना" हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है। आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है। मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है। समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। "संतुष्टिकरण" बनाम "तुष्टिकरण" की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है। आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है।

राज्यसभा में एनडीए...

जयसिंह रावत

राज्यसभा का अगला पड़ाव : 'चेक पोस्ट' से 'विधायी हाईवे' तक

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के दोनों सदनों की अपनी विशिष्ट भूमिका और गरिमा है। लोकसभा जहाँ जनता की सीधी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा को राज्यों की परिषद के रूप में एक 'निरीक्षक सदन' माना जाता है। पिछले एक दशक के राजनीतिक इतिहास को देखें, तो यह सदन मोदी सरकार के लिए किसी 'स्पीड ब्रेकर' से कम नहीं रहा है। लोकसभा में प्रचंड बहुमत के बावजूद, कई ऐतिहासिक और विवादास्पद विधेयकों को पारित कराने में सरकार को राज्यसभा में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ऊपरी सदन को विपक्ष ने लंबे समय तक सरकार की 'चेक पोस्ट' के रूप में इस्तेमाल किया, जहाँ विधायी प्रस्तावों को न केवल धीमा किया गया, बल्कि कई बार उन्हें रोक भी दिया गया। लेकिन 16 मार्च 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव इस पूरी तस्वीर को बुनियादी तौर पर बदलने जा रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक गणित और राज्यों की विधानसभाओं की स्थिति कर कह रही है कि अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की संख्या उस निर्णायक मोड़ पर पहुँचने वाली है, जहाँ से सत्ता का विधायी रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। आगामी राज्यसभा चुनावों का महत्व केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल की विधायी शक्ति का लिटमस टेस्ट है। जिन 10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से अधिकांश में भाजपा या उसके सहयोगियों की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है। महाराष्ट्र, असम, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हालिया राजनीतिक बदलावों ने भाजपा की स्थिति को और मजबूत किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दो वर्षों में जो उथल-पुथल मची और जिस तरह से गठबंधन के नए समीकरण बने, उसने महायुति को वह संख्या बल प्रदान किया है जिससे वे राज्यसभा की अधिकतम सीटें जीत सकें। इसी तरह असम और हरियाणा में विपक्षी बिखराव ने भाजपा के लिए रास्ता साफ कर दिया है। यह चुनावी परिणाम राज्यसभा के भीतर उस पारंपरिक अवरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम होंगे, जो विपक्ष ने एक मजबूत ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि भाजपा इस बार अपनी पिछली ताकत में बड़ा इजाफा करने जा रही है। राज्यसभा में एनडीए की संख्या बढ़ने का सबसे सीधा और गहरा प्रभाव देश की विधायी प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब तक मोदी सरकार को किसी भी बड़े कानून को पारित कराने के लिए गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपा क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह निर्भरता अक्सर नीतिगत समझौतों या अनावश्यक देरी का कारण बनती थी। जब सत्तापक्ष के पास अपने दम पर या स्थायी सहयोगियों के साथ बहुमत होता है, तो वह 'निर्णायक सुधारों' की ओर बढ़ने का साहस दिखा पाता है। भूमि अधिग्रहण, व्यापक श्रम सुधार, बिजली क्षेत्र में बदलाव और बैंकिंग सुधार जैसे विषय, जो पिछले वर्षों में राज्यसभा की दहलीज पर अटक गए थे, अब फिर से सरकार की प्राथमिकता बन सकते हैं। यह मोदी सरकार के 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ी संस्थागत जीत होगी।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

अशोक भाटिया

बेटो को रास नहीं आ रहे है बूढ़े माँ-बाप

कुछ दिनों से वाट्स अप पर एक लघु कथा वाइरल हो रही है जिसका संक्षिप्त यह है कि एक बेटा माँ को घूमाने के बहाने से ले जाकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ देता है । जब बेटा वहाँ से वापस जाने लगता है तो माँ उसे बुला कर कहती है कि तुमने मुझे घूमाने के बहाने से लाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया इस बात का गम नहीं है मैं तो तुम्हें केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने तेरा जन्म के पूर्व पाँच लड़कियों की भ्रण हत्या कारवाई थी तब तुमको जन्मा था । आज शायद उसी पाप की सज़ा मुझे मिल रही है । तो ऐसे तो कई किस्से सुनने को या देखने को मिलते है कि लोग अपने माता – पिता को वृद्धावस्था के समय वृद्धाश्रम में छोड़ देते है , पर हाल ही एक ऐसे कलयुगी बेटे का समाचार मिला है जिसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम के बजाय मुंबई की सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया । कुछ समय पूर्व की घटना है दक्षिण मुंबई स्थित बॉम्बे अस्पताल के पास सड़क पर दिलीप नामक एक युवक अपनी 85 वर्षीय माँ हंसा राजपूत को छोड़ कर भाग गया । लगातार बारिश होने के कारण माँ हंसा बीमार हो गई थीं और सड़क पर बैठी रो रही थीं । किसी भले आदमी ने उसे पास के अस्पताल में भरती करा दिया । अब भी माँ 15 दिन से अस्पताल में अपने बेटे को बार – बार पुकारती इस माँ को भले ही बेटे ने चलती कार से धकेल दिया फिर भी इस माँ की आँखें हर दिन अपने बेटे के आने की रह तक रही है । उदाहरण और घटनाए और भी है । एक बूढ़ी मां को दिल्ली के एक गुरुद्वारे में इसलिए शरण लेनी पड़ी क्योंकि उस बूढ़ी मां को उसके अपने बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। बेटे ने अपनी मां को हरिद्वार ले जाने के बहाने घर से अपने साथ लिया और मोदीनगर के पास जंगल में उसे अकेला छोड़कर चला गया। इस वृध्दा को न तो ठीक से दिखाई देता है और न ही उसके पास घर का पूरा पता वगैरह है कि वह किसी के सहारे अपने घर लौट सके। किसी ने उसे भटकते हुए पाया तो गुरुद्वारे तक पहुंचाया। आज जो सामाजिक सोच में परिवर्तन आ रहा है तथा मानव मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, नैतिकता का नामोनिशां मिटने की ओर है, इसका इससे प्रबल कोई उदाहरण और क्या मिलेगा? जिन बच्चों को पाल-पोष कर बड़ा करने के लिए माता-पिता अपना पेट काटकर एक-एक पैसा जोड़ते हैं। अपना मन मसोसकर, अपनी अति आवश्यक

जरूरतों को भी दरकिनार कर बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनका काम धंधा जमाने के लिए मां-बाप क्या नहीं करते, उन्हीं मां-बाप के साथ आज उन्हीं की जायी संतानें ऐसा बर्ताव करती हैं कि बेशर्मी भी शर्मा जाए। कहीं कोई अपने मां-बाप पर हाथ उठा रहा है तो कोई उन्हें दो वक्त की रोटी देने से मुंह मोड़ रहा है। कहीं कोई उन्हें घर से बेदखल कर फुटपाथ पर जीवन बसर करने को मजबूर कर रहा है तो कोई अपने माता-पिता को इसलिए वृध्दाश्रम छोड़कर आ रहा है क्योंकि उनकी छोटी-छोटी बातें, उनका स्वभाव, उनका रहन-सहन परिवार के अन्य सदस्यों को, मसलन, पुत्र-पुत्रवधू, पोता-पोती को रास नहीं आ रहा। आज व्यक्ति अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में इतना मशगूल है कि उसकी रात की नींद और दिन का चैन गायब है। प्रतिस्पर्धा में वह सबसे आगे रहना चाहता है। हर व्यक्ति को, उसके परिवार को वह सब कुछ चाहिए, जो दूसरों के पास है। जो इतना जुटा चुके हैं, वे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, मौजमस्ती में लुटा रहे हैं। जिनके पास लुटाने के लिए नहीं है, वे जुटाने में लगे हैं। इन प्रयासों में माता-पिता की घर में उपस्थिति बाधक बनती है। आदमी को लगता है कि मां-बाप के कारण वह काफी बंधा हुआ है। पति पत्नी और बच्चों की स्वच्छंदता में वे बूढे माता-पिता कहीं रोड़े बन रहे हैं। घर में आते-जाते उनका टोकना उन्हें नहीं भाता। अनेक घरों में बूढे लोग जिंदा लाश के समान हैं। मर तो सकते नहीं, क्योंकि मरना भी आसान नहीं है, जिंदा केवल शरीर है। मन मर चुका है, भावनाएं दबी पड़ी हैं, ममता मरने को मजबूर है, स्नेह सूख रहा है। बूढ़े लोगों की उपयोगिता घर की रखवाली तक सीमित रह गई है। कहीं-कहीं पर वृध्दजनों का औपचारिक ध्यान रखा जाता है क्योंकि पुश्तैनी प्रापर्टी उनके मालिकाना हक में होती है तो उन्हें खुश रखना जरूरी होता है। किसी बुजुर्ग के पास नकदी या आभूषणों से भरी कोई संदूक (पुराने जमाने में ऐसे ही संपत्ति सहेज कर रखी जाती थी) है तो उसको खुशी-खुशी पाने की ललक में भी बुजुर्ग की देखभाल की जाती है। हालांकि आजकल तो ऐसा होना जोखिम भरा काम भी हो गया है। कुछ सिरफिरी संतानें तो बूढ़ों के मरने का इंतजार करने के बजाय प्रापर्टी जल्दी पाने के चक्कर में उन्हें ठिकाने तक लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बूढे-अशक्त मां-बाप के हक की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है परन्तु या तो ऐसे कानूनों से लोग, खासकर वृध्द लोग अनभिज्ञ हैं या फिर कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाने की असमर्थता के चलते प्रताड़ित होते हुए भी वृद्ध जन शिकायत नहीं करते। इससे भी ज्यादा, अपनी संतान के प्रति मोह के चलते बूढ़े मां-बाप कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। वे अपने परिचितों, रिश्तेदारों के समक्ष तो अपना दुखड़ा रो देते हैं परन्तु अदालतों या पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाते। उन्हें लगता है कि 'ज्यादा गई, थोड़ी रही', क्यों अपनी ही संतान को अदालत में घसीटें। इसलिए सब कुछ सहते रहते हैं। ऐसे में सरकार को एक हेल्प लाइन नंबर शुरू करना चाहिए ,जिससे बुजर्गों को मदद मिल सके । साथ ही हर सरकारी अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बने ताकि बुजुर्गो को वहाँ रहने में मदद मिल सके और उनका समय पर सही इलाज हो सकें । वैसे सरकार व अदालातें बुजुर्गो के लिए बहुत कुछ कर रही है .छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बीते दिनों आए फैसले की हम बात करे । रायपुर के कासिमपारा क्षेत्र के रहने वाले सेवालाल बघेल का आरोप था कि उनके बेटे और बहू रायपुर में उनके ही मकान में रहते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते हैं। वह सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। मकान को बुजुर्ग ने खुद खरीदा था लेकिन बेटे-बहू उन्हें अपने ही घर से निकालने के धमकी दिया करते थे। इस वजह से वह अपने बड़े बेटे के यहां रह रहने को मजबूर थे। बेटे-बहू की प्रताड़ना से तंग आकर सेवालाल ने रायपुर कलेक्टर के यहां मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजन ऐक्ट, 2007 के तहत शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने उन्हें राहत देते हुए बहू-बेटे को 7 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया। साथ में बुजुर्ग को हर महीने 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। कलेक्टर के इस आदेश को बेटे नीरज बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 रन के अंदर 6 विकेट गंवाए, सीरीज 1-1 से बराबरी पर

भारतीय विमेंस टीम 17 रन से दूसरा टी-20 हारी

नई दिल्ली, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया विमेंस को 17 रन से दूसरा टी-20 हरा दिया। गुरुवार को कैनबरा में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 163 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 9 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉर्जिया वॉल ने सबसे ज्यादा 88 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वॉल ने मूनी के साथ मिलकर पहले विकेट लिए 128 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया की जीत की नींव रखी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने फिर चौथे विकेट के लिए 55 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन इस पार्टनरशिप के टूटते ही भारत ने अगले 7 रन के अंदर 6 विकेट गंवा दिए। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने सबसे ज्यादा 36 रन की पारी खेली। वहीं स्मृति ने 31 और शेफाली ने 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले गार्डनर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। उनके अलावा किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलेन्यू ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहला टी-20 जीता, वहीं ऑस्ट्रेलिया के नाम दूसरा टी-20 रहा। सीरीज का तीसरा और डिसाइडर मुकाबला 21 फरवरी को एडिलेड स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारतीय पारी अच्छी शुरुआत के बाद पटरी से उतरी

164 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तेज शुरुआत की। दोनों ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पावरप्ले में बिना विकेट खोए 54 रन बना दिए। भारत ने 7वें ओवर में 57 रन पर शेफाली का विकेट गंवाया और 10वें ओवर तक स्कोर 71 रन पर 3 विकेट हो गया।

- बेथ मूनी ने 46 रन बनाए। उन्होंने वॉल के साथ मिलकर 128 रन की पार्टनरशिप की।
- जॉर्जिया वॉल ने सबसे ज्यादा 88 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने भारत को बैकफुट पर धकेला

भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया को दोनों ओपनर्स जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने शतकीय साझेदारी करते हुए पहले विकेट के लिए 128 रन जोड़े।

> 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 128 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 180 या 190 के स्कोर तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट पर 163 रन के स्कोर पर रोक दिया ऑस्ट्रेलिया से वॉल ने 57 गेंदो पर 88 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं मूनी ने 39 गेंदों पर 46 रन बनाए।

पाकिस्तान बोर्ड ने क्रिकेटर से कहा-दिग्गजों पर कमेंट न करें

शादाब खान बोले थे- हमने भारत को हराया, ये सीनियर खिलाड़ी नहीं कर पाए

नई दिल्ली, एजेंसी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को अपने बयान के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। शादाब ने कहा था कि हमने भारत को हराया है, ये काम सीनियर प्लेयर नहीं कर पाए। शादाब का इशारा 2021 टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत पर जीत को लेकर था। अब PCB ने पूर्व खिलाड़ियों की आलोचना पर दिए शादाब के बयान को अनुचित माना है। 2026 टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया था। बोर्ड ने शादाब को हिदायत देते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। यह पूरा मामला 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद हुई पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। नामीबिया के खिलाफ 36 रन बनाने और 3 विकेट लेने के बाद शादाब

खान ने पूर्व खिलाड़ियों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, 'आलोचना क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा है। पूर्व क्रिकेटर्स की अपनी राय है। वे दिग्गज थे, लेकिन हमने जो किया, वे नहीं कर सके। हमने वर्ल्ड कप में भारत को हराया है।' न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक PCB ने टीम मैनेजर नवीद चीमा के जरिए शादाब से नाराजगी जाहिर की है। चीमा ने शादाब को फोन कर बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी हैं। शादाब को याद दिलाया गया कि उनके ससुर सकलैन मुश्ताक समेत सभी पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तान के दिग्गज हैं और वे सम्मान के हकदार हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों को ऐसी भाषा के इस्तेमाल से बचना चाहिए। PCB ने सिर्फ शादाब ही नहीं, बल्कि पूरी टीम को नसीहत दी है। टीम मैनेजर को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी खिलाड़ियों को समझाएं कि वे अपनी टिप्पणियों को सिर्फ मैच तक ही सीमित रखें। अगर कोई खिलाड़ी दोबारा मर्यादा लांघता है तो बोर्ड उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी शादाब के बयान को गैरजरूरी बताया और कहा कि दिग्गजों के खिलाफ बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट फिलहाल मीडिया इंटरैक्शन को लेकर काफी सतर्क है। भारत के साथ हुए अहम मैच से दो दिन पहले तक मैनेजमेंट ने किसी भी खिलाड़ी को मीडिया के सामने नहीं भेजा था।

फास्ट न्यूज

फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी लीक

मुंबई। बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर एक नई बड़ी खबर सामने आई है जिसमें फिल्म की स्टोरी रिलीज से पहले ही लीक होने का दावा किया जा रहा है। इस खबर के अनुसार, लीक हुई कहानी में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के किरदारों के बारे में असाधारण अपडेट सामने आया है।

'द केरल स्टोरी 2' के मेकर्स और सीबीएफसी को नोटिस

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उस याचिका पर सुनवाई के बाद जारी हुआ, जिसमें संबंधित फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की मांग की गई। कन्नूर जिले के चिट्टारिपरम्बा के रहने वाले श्रीदेव नम्बूथिरी ने यह याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि फिल्म में बिना किसी ठोस सबूत के पूरे राज्य को गलत तरीके से बदनाम किया गया और रूढ़िवादी तरीके से दिखाया गया। याचिका में कहा गया, "फिल्म का ट्रेलर देखने से साफ है कि कहानी तीन अलग-अलग राज्यों की महिलाओं पर आधारित है और ज्यादातर घटनाएं उत्तर भारत में घटित होती हैं। इसके बावजूद, फिल्म का टाइटल और सीन केरल को गलत तरीके से नकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X (ट्विटर), यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक को कल 20 जनवरी से अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। इसके साथ ही अगर कोई डीपफेक वीडियो-फोटो अपलोड करता है, तो उसे 3 में हटाने होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए IT रूल्स 2021 में बदलाव किया है।

रणवीर सिंह को धमकी देने के लिए अमेरिकी नंबर का किया इस्तेमाल

हैरी बॉक्सर ने मांगे थे 10 करोड़ रुपए

मुंबई, एजेंसी

'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह को हाल ही में बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के मामले को लेकर पुलिस एलर्ट है। मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर ने व्हाट्सएप पर वॉयस नोट भेजकर रणवीर सिंह से 10 करोड़ रुपए मांगे थे। अपडेट यह भी है कि हैरी बॉक्सर ने जिस नंबर का इस्तेमाल किया था वह अमेरिकी नंबर था। अभिनेता को यह धमकी रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के ठीक बाद भेजी गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पुष्टि हुई है कि वॉयस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज है। यह मैसेज अमेरिकी नंबर से भेजा गया था। इसके लिए पुलिस अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि वॉयस नोट वीपीएन का इस्तेमाल करके विदेश से

भेजा गया था। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एआईआर नहीं दर्ज की है। हालांकि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच रणवीर सिंह के मैनेजर का भी बयान दर्ज कर चुकी है। रणवीर सिंह ने मैसेज मिलते ही तुरंत मुंबई पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। इसके साथ उनके आवास पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए। उनकी सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया था।

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस

भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप, कंज्यूमर कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी मांगा जवाब

झालावाड़, एजेंसी

झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस का जवाब मांगा है। एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवार पेश करते हुए आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन विज्ञापन में जो दिखाते हैं, वह पूरी तरह भ्रामक है। एडवोकेट गुरचरण सिंह ने बताया- 20 जनवरी को परिवाद पेश किया गया था। कोर्ट में तथ्यों की जांच के बाद 12 फरवरी को कोर्ट ने कंपनी के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता ऋतिक रोशन, कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड को डाक के माध्यम से नोटिस भेजे हैं और 1 महीने में जवाब मांगा है। उन्होंने बताया- कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे जो चीज महसूस हुई, वो ये है।

कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुछ अलग महसूस नहीं हुआ

एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने कहा- माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक कंपनी का विज्ञापन ऋतिक रोशन करते हैं। उनके द्वारा यह बोला जाता है कि माउंटेन ड्यू जितना ज्यादा आप पीएंगे, आप में हिम्मत बढ़ेगी। आपका डर खत्म होगा। यह सब चीजें उसमें बताई गई है। यह विज्ञापन देखकर मैंने भरोसा किया और माउंटेन ड्यू खरीद कर पी। उन्होंने बताया- कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे जो चीज महसूस हुई, वो ये है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे कोई हिम्मत बढ़ती हो या डर खत्म होता हो। न उसमें कोई ऐसी सामग्री (इंग्रेडिएंट) है और न कोई ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट है कि इससे डर खत्म होता है।

> विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और ऊर्जा आती है, जिससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है। एडवोकेट सिंह ने बताया कि विज्ञापन से प्रभावित होकर कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसको पीया, लेकिन विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ।

उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप

एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने कोर्ट को बताया- कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह 'भ्रामक विज्ञापन' की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता न्यायालय ने प्रारंभिक तौर पर मामले को सही पाया और परिवाद स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया तथ्यों में सच्चाई पाई, जिसके बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट अब इस बात की जांच करेगी कि क्या कंपनी द्वारा किए गए दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं।

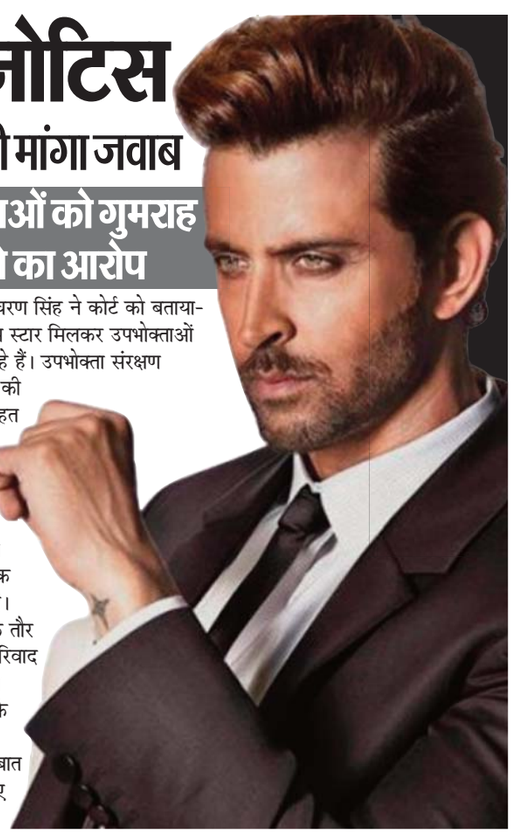

ट्रम्प के मैसेज लीक करने पर मैक्रों का जवाब

कहा- रिश्तों में सम्मान जरूरी, कुछ नेता आगे बढ़ने के बजाए पीछे जाते दिख रहे

नई दिल्ली, एजेंसी

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि देशों के बीच रिश्तों में सम्मान बहुत जरूरी होता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दोनों नेताओं के बीच हुए प्राइवेट मैसेज लीक कर दिए। भारत के तीन दिन के दौरे पर आए मैक्रों ने भारतीय पॉडकास्टर राज शमानी के शो में यह बात कही। उनसे पूछा गया कि उनके निजी मैसेज लीक होने पर उन्हें कैसा लगा। इस पर मैक्रों ने सीधे ट्रम्प का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि कूटनीति में एक-दूसरे का सम्मान जरूरी है। ट्रम्प ने 20 जनवरी को मैक्रों का निजी मैसेज लीक किया था। उस मैसेज में मैक्रों ने ट्रम्प से कहा था कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेकर क्या करना चाहते हैं। उन्होंने आगे मिलकर काम करने की बात भी कही थी और G7 बैठक की मेजबानी का सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी कहा था

कि इस बैठक में यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस जैसे देशों को शामिल किया जा सकता है। इसके बाद ट्रम्प ने फ्रांस की वाइन और शैम्पेन पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी और कहा कि इससे मैक्रों पर दबाव पड़ेगा। बाद में ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दोनों के बीच हुए निजी मैसेज भी शेयर कर दिए, जिनमें मैक्रों ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी पर चिंता जताई थी। फ्रेंच वाइन और शैम्पेन दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। फ्रांस की वाइन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता हैं। फ्रांस को दुनिया की वाइन राजधानी कहा जाता है।

मैक्रों बोले- हिंसा और अपमान की जरूरत नहीं

मैक्रों ने पॉडकास्ट में यह भी कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपने नेता बदलने का अधिकार होता है, इसलिए हिंसा और अपमान की जरूरत नहीं है। वे समाज में नफरत भरी भाषा और हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या दुनिया को अमेरिका के मौजूदा लीडरशिप से डरने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि आज के हालात में यह थोड़ा हैरान करने वाला है कि कुछ नेता आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाते दिख रहे हैं।

- फ्रेंच वाइन फ्रांस के अलग-अलग इलाकों में उगाए गए अंगूरों से बनाई जाती है। इसमें 11-15% तक अल्कोहल होता है।

ट्रम्प ने फ्रांसीसी वाइन पर 200% टैरिफ की धमकी दी थी

ट्रम्प और मैक्रों के बीच लंबे समय के तल्खी रही है, लेकिन हाल में विवाद तब बढ़ा जब फ्रांस ने ट्रम्प के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया। यह बोर्ड गाजा के विकास के लिए बनाया गया है। फ्रांस समेत कई देशों ने इस बात पर चिंता जताई कि बोर्ड के दस्तावेज में गाजा और इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का साफ जिक्र नहीं है।

> मैक्रों ने कहा कि देश आपस में सहमत हों या असहमत, लेकिन अपनी बात सम्मान के साथ रखनी चाहिए। असहमति जताना गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। मैक्रों ने ट्रम्प पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता आगे बढ़ने के बजाए पीछे जाते हुए दिख रहे हैं।

ब्रिटेन का अमेरिका को अपने एयरबेस देने से इनकार

ट्रम्प ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं

लंदन, एजेंसी

ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया है। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है, जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने की बात थी। अमेरिका ईरान पर संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वह डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया, चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक से यह ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा रहा है। दरअसल पुराने समझौतों के मुताबिक,

ब्रिटेन के किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल तभी हो सकता है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसकी मंजूरी दें। अंतरराष्ट्रीय कानून भी कहता है कि अगर कोई देश जानता है कि सैन्य कार्रवाई गलत है और फिर भी मदद करता है, तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यह हिंद महासागर के बीचों-बीच स्थित एक बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहां से अमेरिका दूर तक और तेजी से सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। यह ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 3,800 किलोमीटर दूर है।

साइन : चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएंगी, मोदी-ट्रम्प की मुलाकात जल्द

एआई समिट में भारत-अमेरिका का 'पैक्स सिलिका' समझौता

नई दिल्ली, एजेंसी

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के आखिरी दिन भारत और अमेरिका ने 'पैक्स सिलिका' डिक्लेरेशन पर साइन किए हैं। इस समझौते का मकसद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और AI की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और गैर-मित्र देशों पर निर्भरता कम करना है। सर्जियो गोर ने भारत में हो रही इस समिट को बेहद प्रभावशाली बताया। जब उनसे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने संकेत देते हुए कहा- बने रहिए। मुझे यकीन है कि सही समय पर यह मुलाकात जरूर होगी। भारत और अमेरिका के बीच हुए 'पैक्स सिलिका' समझौते के दौरान गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि इस समझौते का मकसद सुरक्षा और भरोसेमंद सप्लाई चेन सुनिश्चित करना है। साथ ही,

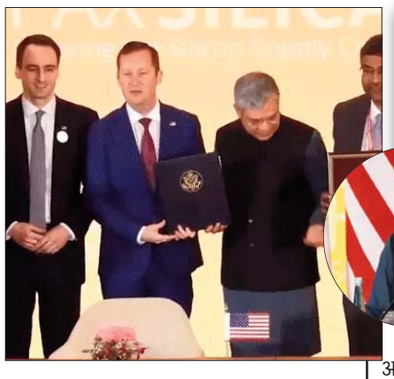

इससे अहम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे। सुंदर पिचाई ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि एआई (AI) का फायदा सबको मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गूगल अपने प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और खास बिजनेस सॉल्यूशंस के जरिए भारत में एआई की ग्रोथ को पूरा सपोर्ट कर रहा है।

> अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आने वाले समय में करीब 10 लाख अतिरिक्त स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी और दुनिया की यह उम्मीद भारत से ही है। उन्होंने कहा, "देश के पास अब एक साफ दिशा और लक्ष्य है। हमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडरशिप लेनी है।"

अश्विनी वैष्णव बोले- सेमीकंडक्टर का हब बनेगा भारत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिकी आर्थिक मामलों के सचिव जैकब हेलबर्ग ने इसपर साइन किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने बताया- भारत में पहले से ही 10 प्लांट्स पर काम चल रहा है। वैष्णव ने यह भी साझा किया कि भारतीय इंजीनियर अब देश में ही एडवांस '2-नैनोमीटर' चिप डिजाइन कर रहे हैं।

अमेरिका बोला- भारत का प्रवेश सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं

समिट में शामिल अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस गठबंधन में भारत की एंट्री को रणनीतिक रूप से अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा, भारत के पास ऐसा टैलेंट है जो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है।

बलूच लड़ाकों की कैद में रोते दिखे पाकिस्तानी सैनिक

कहा- हम देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया है। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए कह रहा है कि वह पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज सेना उसे अपना नहीं मान रही। सैनिक कह रहा है- 'मेरे पास पाकिस्तानी सेना का ID कार्ड है, फिर क्यों कहा जा रहा है कि मैं पाकिस्तानी सैनिक नहीं हूं।' यह वीडियो पाकिस्तान की सेना के उस बयान को सीधी चुनौती देता है, जिसमें कहा गया था कि उसके कोई भी सैनिक लापता नहीं हैं और न ही किसी उग्रवादी संगठन की हिरासत में हैं। BLA ने 14 फरवरी को इन सैनिकों को पकड़ा

- पाकिस्तानी सैनिकों के कैद करने का यह वीडियो
- बीएलए से जुड़े हक्काल मीडिया ने जारी किया है।

कैमरे पर रोते हुए असलियत बताते पाकिस्तानी सैनिक।

था। इनकी रिहाई के लिए BLA ने बलूच लड़ाकों की रिहाई की मांग की है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार को 22 फरवरी तक का वक्त दिया गया है।यह वीडियो BLA के आधिकारिक चैनल 'हक्काल' पर जारी किया गया है। वीडियो में बंदी बनाए गए सैनिकों से BLA लड़ाके कहते हैं, "पाकिस्तान सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन वो आप लोगों को अपना मानने से इनकार कर रही है। आप कैसे साबित करेंगे कि पाकिस्तानी सैनिक हैं?" इसके जवाब में सैनिक रोते हुए कहते हैं, "आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके 'बंदे' नहीं हैं।" सैनिक कैमरे के सामने अपने ऑफिशियल सर्विस और आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहते हैं- 'ये आर्मी का ही तो है न। इन्होंने ही तो हमें ये सब दिया था। हमने खुद ये तो नहीं बनाया है। आप किस तरह ये कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं हैं।' एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करते हुए कहता है, 'हमें भर्ती किया गया था।

पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए, बोले- न्याय दो, पावर हाउस में घुसकर महिला ने मारे थे थप्पड़

बिजलीकर्मियों का थाने पर प्रदर्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में पावर हाउस में घुसकर बिजलीकर्मियों को थप्पड़ मारने की घटना के बाद कर्मी आक्रोशित हैं। बुधवार को एक महिला ग्राहक ने विकासनगर सेक्टर-14 पावर हाउस पर बवाल मचाया था। उसने समस्या की शिकायत की तो उससे कर्मियों ने बिजली बिल डिटेल मांग ली थी। इसी पर गुस्साई महिला ने वहां पहुंचकर थप्पड़ मारे थे। उसके बाद आज, शुक्रवार को दर्जनों बिजलीकर्मियों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वे पावर हाउस से हाथों में 'न्याय दो' लिखी तख्तियां लेकर विकासनगर थाने पहुंचे। यहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। उनका कहना है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? विकासनगर थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे तो सिपाहियों ने बाहर

निकलकर कर्मियों को चुप करा दिया। कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज की। इस दौरान विकासनगर सेक्टर- 14 की रहने वाली महिला ने स्थानीय पावर हाउस स्थित कंट्रोल रूम पर बुधवार दोपहर 2.10 बजे शिकायत की। कहा कि मकान सं-14/115 में बिजली नहीं आ रही है। जब बिजली कर्मचारियों ने उनसे जमा बिल की जानकारी की और कनेक्शन संख्या बताने का अनुरोध किया तो महिला ने गुस्से में फोन काट दिया। थप्पड़ भी मारे। डॉयल-112 पर फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मारपीट में उपकेंद्र पर कार्यरत हरीश यादव, आकाश कन्नौजिया, अनूप कुमार और रजनीश यादव को चोट आई है।

पुलिस ने सख्ती बरती तो लौटे कर्मचारी

कर्मचारी थाने के सामने नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने सख्ती बरती। इसके बाद कर्मचारियों ने नारा लगाना बंद कर दिया और शांत हो गए। कर्मचारियों ने कहा कि जिन लोगों ने उनपर हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारियों को थाने पर बुलाकर ही पूछताछ की जा रही है। कर्मचारियों ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के बाद में मनोबल गिर गया है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

विकासनगर थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे तो सिपाहियों ने बाहर निकलकर कर्मियों को चुप करा दिया।

महिला फोन काटने पर गुस्सा हो गई थी

बुधवार को विकासनगर सेक्टर-14 स्थित पावर हाउस का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि विकासनगर सेक्टर-14 निवासी महिला ने कंट्रोल रूम में बिजली नहीं आने की शिकायत की

दावा- लोगों के साथ मिलकर की पिटाई

कुछ देर बाद महिला एक अन्य व्यक्ति के साथ पावर हाउस पहुंची। वहां घुसते ही उसने बिजली कर्मचारी अनूप कुमार के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी देने लगी। कंट्रोल रूम में रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। बिजली कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी इस बीच कर्मचारियों ने मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो महिला ने उनका मोबाइल छीन लिया। बिजली कर्मचारी हरीश यादव का गला दबा दिया।

लखनऊ नगर निगम का ₹4692.71 करोड़ का बजट तैयार

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम की तरफ से साल 2026-27 के बजट को लेकर 22 फरवरी को कार्यकारिणी बैठक की जाएगी। इसमें आने वाले वित्त वर्ष में शहर के विकास और एजेंडा तय होगा। कुल 4692.71 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिलेगी। नगर निगम की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है। 12 फरवरी को हुई बैठक में पूरी रूपरेखा अधिकारियों ने तैयार कर ली है। कार्यकारिणी में मंजूरी के बाद इसे सदन की बजट बैठक में रखा जाएगा। बजट में सबसे अधिक जोर साफ-सफाई और कूड़ा निस्तारण पर है। ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। इसमें कुल 400 करोड़ रुपए आने वाले एक साल में खर्च होंगे। पार्षदों की निधि भी 2.10 करोड़ से 3 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। मेयर की विकास निधि 20 करोड़ और नगर आयुक्त की विकास निधि 10 करोड़ को भी बढ़ाने की मांग है। इसके साथ बजट में सड़क निर्माण पर 271 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में कल्याण मंडप बनाने, नगर निगम को डिजिटल बनाने सहित मूल भूत सुविधाओं को सुधारने पर जोर है।

फर्जी फर्म बनाकर 37 लाख रुपए का जीएसटी चुराया

लखनऊ में 3 आरोपी गिरफ्तार, सरगना समेत 4 आरोपी अब भी फरार

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में फर्जी दस्तावेज के जरिये फर्म रजिस्टर कर करोड़ों का फर्जी लेनदेन और 37 लाख रुपए का GST चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सहित चार अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को भगवती चरण वर्मा ने महानगर का फर्जी पता दिखाते हुए M/S केएस इंटरप्राइजेज नाम से GST नंबर लिया था। फर्म के नाम पर करोड़ों की खरीद-बिक्री दिखाई गई थी। जांच में सामने आया कि दिए गए पते पर न तो कोई दफ्तर है, न ही फर्म का कोई अस्तित्व है। मकान मालिक ने भी इसे फर्जी बताया। विवेचना के दौरान पता चला कि दीपक नामक युवक ने साथियों के साथ मिलकर अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी फर्म के जरिये करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए का

लेनदेन किया। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाकर सरकार को कुल 37,52,545 रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया था। जांच में सामने आया कि लेनदेन की राशि में से करीब 15 लाख रुपए चार चेक के जरिये प्रशांत तिवारी को दिए गए, जिनका उपयोग उसने घरेलू कामों में किया। कैलाश मौर्या पर फर्जी मुहर तैयार कर बैंक खाते खुलवाने और GST चोरी में सहयोग का आरोप है। आरोपियों ने तेजी से पैसा कमाने के लालच में फर्जी बिजली बिल तैयार किया। इसके आधार पर GST रजिस्ट्रेशन भी कराया।

फास्ट न्यूज

भाजपा विधायक के भतीजे के सुसाइड मामले में एफआईआर

लखनऊ। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित रिशिता मैनहैटन अपार्टमेंट में एक फरवरी को गोंडा के भाजपा विधायक विनय द्विवेदी के भतीजे शुभम त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शुभम के दोस्त सौरभ पांडे और उसकी पत्नी अर्चना उर्फ ममता पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

युवती ने पति को मारे थप्पड़ ही थप्पड़

मुरादाबाद। मुरादाबाद में परिवार न्यायालय के बाहर एक युवती ने जमकर हंगामा किया। उसने पति को कॉलर पकड़कर घसीटा। कई थप्पड़ मारे। युवती इस बात से नाराज थी कि उसके पति ने उस पर कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए थे। इस घटना के बाद पति ने थाने में तहरीर देकर पत्नी और सास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव देवीपुरा मजरा निवासी अरविंद कुमार का अपनी पत्नी सोनम से कुछ विवाद चल रहा है। जिसकी सुनवाई विधिक सेवा प्राधिकरण में चल रही है। गुरुवार को भी इस मामले में विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों को सुलह समझौते के लिए बुलाया गया था। सोनम का आरोप है कि विधिक सेवा प्राधिकरण में सुनवाई के दौरान अरविंद ने उस पर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी ने मुझे मरवाने के लिए लड़के लगा रखे हैं।

कानपुर-सागर हाईवे पर 30 किमी. लंबा जाम

कानपुर। कानपुर-सागर हाईवे पर पिछले 15 घंटे से 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। जाम में एंबुलेंस और स्कूली वाहन फंसे रहे। पुलिस के मुताबिक, बिधनू थाना क्षेत्र के रमईपुर चौराहे के पास देर रात दो ट्रक खराब हो गए थे। जिसके बाद से जाम लग गया। रात होने के कारण कुछ वाहन चालक सो गए। जिसके कारण हाईवे पर वाहनों की कतारें लगातार बढ़ती चली गईं। सुबह होते-होते यह जाम करीब 30 किलोमीटर लंबा हो गया।

गांजा बेचने का विरोध किया तो नाली में डुबोया, मंदिर के पीछे 20 फीट गहरे गड्ढे में शव फेंका

पीट-पीटकर पुजारी की हत्या

- पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की।
- कल्लू बाबा के परिजन पोस्टमॉर्टम हाउस पर पहुंचे।
- मंदिर के बाहर नाली बनी है। परिजनों का आरोप है कि कल्लू बाबा को नाली में डूबो-डूबो कर मारा गया है।

तमसा संकेत, एजेंसी

दुबग्गा। लखनऊ में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। उनका शव मंदिर के पीछे करीब 20 फीट गड्ढे में मिला। माथे पर चोट के निशान थे। गला घोंटा गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी। घटना दुबग्गा इलाके के आश्रयहीन कॉलोनी में 19 फरवरी की रात की है। पुजारी की पहचान 60 वर्षीय कल्लू प्रजापति उर्फ कल्लू बाबा के रूप में हुई है।

राहगीर ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी

S-2 आश्रयहीन कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गोलू ने शीतला माता मंदिर के पास गड्ढे में कल्लू बाबा का शव देखा। उन्होंने इसकी कॉलोनी के लोगों और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कल्लू बाबा के माथे पर किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान मिले। गला घोंटे जाने का भी निशान मिला।

भाई पुत्तीलाल ने बताया कि कल्लू बाबा का बगल में रहने वाली एक महिला और उसके भाई से लड़ाई चल रही थी। महिला गांजा बेचती थी। उसके दो भाई भी उसका साथ देते थे। 19 फरवरी की रात में इन लोगों ने मंदिर की लाइट बंद कर दी थी, जिसको लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में भी इस बात की पुष्टि हुई है। पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही है।

इसी मंदिर में कल्लू बाबा रहते थे।

मंदिर से निकाल कर सड़क कर फेंका

परिजनों ने बताया कि कल्लू को आरोपियों ने मंदिर से निकाल कर सड़क पर पहले बेहरमी से पीटा। माथे पर भारी चीज से वार किया। फिर किसी चीज से गला घोंट दिया। उसके बाद नाली में डुबो दिया। जब कल्लू बाबा की मौत हो गई तो उनको मंदिर के पीछे करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। कल्लू बाबा नेवतनी, मोहन रोड, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के रहने वाले थे। उनके 2 भाई पुत्ती लाल और कमल बाबू हैं। एक भाई भोलाई की मौत हो चुकी है। जिस मंदिर में कल्लू बाबा रहते थे, उसे गुड्डू लोधी ने बनवाया है।

मंत्री दयाशंकर का इंतजार करते-करते थके मंत्री आशीष पटेल

सड़क किनारे कुर्सी डलवाकर बैठे, बोले- जिनके पास बड़े लोग

- मंत्री आशीष पटेल ने 20 मिनट तक खड़े होकर मंत्री दयाशंकर सिंह का इंतजार किया।
- बस को दोनों मंत्री हरी झंडी दिखाकर चित्रकूट के लिए रवाना करेंगे।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह का इंतजार करते-करते मंत्री आशीष पटेल थक गए। 20 मिनट तक उन्होंने सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार किया। थकने पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पर स्थित अपने घर से कुर्सी मंगवाई। कुर्सी पेड़ के नीचे रखकर बैठ गए। एक घंटे बाद दया शंकर सिंह पहुंचे। उनके देर से पहुंचने पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री

आशीष पटेल ने कहा- जिसका दिल बड़ा होता है, उनके पास लोग बड़े होते हैं। जब लोग बड़े होते हैं तो देर से आना स्वाभाविक है। दरअसल, आज सुबह 10 बजे माल एवेन्यू-1 से लखनऊ-चित्रकूट नई बस सेवा की शुरुआत होनी थी। मंत्री दयाशंकर और आशीष हरी झंडी दिखाकर बस को चित्रकूट (हनुमानगंज) के लिए रवाना करना था। आशीष पटेल समय पर पहुंचे, लेकिन दयाशंकर सिंह 11 बजे पहुंचे। फिर दोनों ने बस सेवा की शुरुआत की। मंत्री दया शंकर सिंह के कार्यक्रम में लेट पहुंचने का सिलसिला नया नहीं है। उनके देर से पहुंचने को लेकर सीएम योगी भी चुटकी ले चुके हैं। कहा था-मंत्रीजी आज टाइम पर आ गए, लगता है बसों की टाइमिंग भी ठीक कर देंगे।मंत्री आशीष पटेल ने कहा- परिवहन मंत्रीजी का हृदय बहुत बड़ा है। जब इनके पास कोई मांगने जाता है तो उसे ये देते जरूर हैं। मेरी मांग परिवहन मंत्रीजी ने पूरी की। परिवहन मंत्री के देर से आने पर कहा- जिनका दिल बड़ा होता है, उनके पास लोग बड़े होते हैं। जब लोग बड़े होते हैं तो उनका विलंब से आना स्वाभाविक है। ये इनका स्वभाव है कि किसी को मना नहीं कर पाते हैं। यह नई बस लखनऊ से चित्रकूट के बीच ऊंचाहार, लेहदरी गंगा पुल, सिराथू, राजापुर से होकर चित्रकूट के हनुमानगंज पहुंचेगी। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों, लखनऊ से चित्रकूट दर्शन के लिए जाने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी।

कुलदीप सेंगर के भाई को सरेंडर करने का आदेश

दिल्ली एचसी ने दिये 24 घंटे, रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ में मिली है सजा

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले के दोषी जयदीप सिंह सेंगर उर्फ अतुल सिंह को कल तक यानी 24 घंटे में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। जयदीप सिंह सेंगर को इस मामले में सह-दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ दस साल की सजा सुनाई गई थी। जयदीप सिंह सेंगर ने अपनी दस साल की सजा को निलंबित (सस्पेंड) करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि जयदीप सिंह सेंगर कल तक संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। अदालत ने इस आश्वासन को दर्ज करते हुए सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मामले की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने

कहा कि सजा निलंबन की मांग पर फैसला लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि दोषी की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक की प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है। उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में आरोप था कि पुलिस हिरासत के दौरान एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जयदीप सिंह सेंगर और कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषियों ने इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी।

सुल्तानपुर में बंदरों का आतंक, युवक को काटकर किया लहूलुहान

सुल्तानपुर। जनपद के अलीगंज बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बबुरी में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ताजा मामला काल अहिरन का पुरवा का है, जहां एक युवक को बंदर ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार काल अहिरन का पुरवा निवासी बब्बन यादव (32 वर्ष) पर अचानक बंदर ने हमला कर दिया। बंदर के काटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई दिनों से एक आक्रामक बंदर घूम रहा है, जो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर भी हमला कर चुका है। लोग खेतों और घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस खतरनाक बंदर की सूचना पहले ही वन विभाग को दी जा चुकी है।

विवाद : शेर के दहाड़ते ही कुत्ते भाग जाते हैं, भागवत ने कहा था- हिंदू 3 बच्चे पैदा करें

बच्चे पैदा करने से समाज नहीं बढ़ता : शंकराचार्य

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। 'बच्चा पैदा करने से समाज न घटता है और न ही बढ़ता है। समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म पर टिके रहने से लंबे समय तक कायम रहता है और आगे बढ़ता है। इस विषय में उनकी ओर से कोई उपदेश नहीं दिया जाता।' यह पलटवार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर किया। शंकराचार्य ने कहा- संख्या बल से कोई नहीं जीतता। कुत्तों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन, जब एक शेर दहाड़ता है तो सभी भाग जाते हैं। दरअसल, 17 फरवरी को लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा था कि जो लोग अब शादी कर रहे हैं, उन्हें कम से कम 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विवाह का उद्देश्य सृष्टि को आगे बढ़ाना होना चाहिए, वासना की पूर्ति नहीं। देवकी और वसुदेव ने 8 संतानें पैदा

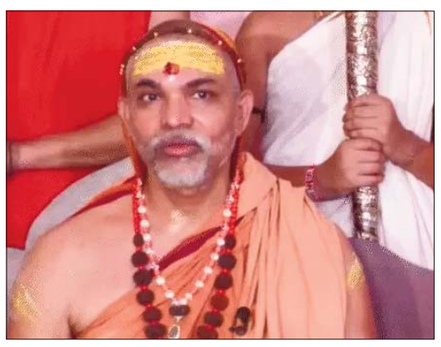

कीं, तभी भगवान का अवतार हुआ। ऐसी परिस्थिति में कोई कितना बच्चा पैदा करेगा, यह माता-पिता पर ही छोड़ देना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी पर शंकराचार्य ने कहा- उनकी बातों पर हम लोग क्यों जाएं? हमें अपने घर की चिंता करनी है। संख्या बल से कोई नहीं जीत सकता। कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही एक शेर दहाड़ता है तो सभी भाग जाते हैं। चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, अगर वे यह सोच रहे हैं कि केवल संख्या बढ़ाने से काम बन जाता है, तो यह सही नहीं है। कई बार संख्या बढ़ने पर लोग आपस में ही लड़कर मर जाते हैं।

धर्मशास्त्रों की अवहेलना की जा रही

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा- उनकी ओर से धर्मशास्त्रों की अवहेलना की जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करें। फिर एक दिन कोई प्रभावी व्यक्ति आकर हमारे बच्चों को समझाकर धर्म परिवर्तन करा दे। फसल हम उगाएं और काटे कोई दूसरा। इसलिए केवल संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता। बच्चे को इतने संस्कार दीजिए। इतना दृढ़ बनाइए कि वह किसी भी परिस्थिति में धर्म की पताका लेकर आगे बढ़ता रहे। 100 तारे उतना प्रकाश नहीं देते, जितना एक चंद्रमा के उगते ही अंधेरा दूर हो जाता है। आप एक बच्चा करें या चार, यह आपकी अपनी पसंद है। इसमें कोई बंधन नहीं।

सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होने से संख्या बढ़ाने की बात करते

भगवान श्रीकृष्ण के वंशज यादवों को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं मारा था। वे आपसी संघर्ष में ही नष्ट हो गए थे। जब संख्या बहुत अधिक हो जाती है, अनुशासन और एकता नहीं रहती, तो समाज अंदर से कमजोर हो सकता है। संख्या बढ़ जाने पर कई बार लोग आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। इसलिए संख्या की बात वही लोग करते हैं, जिन्हें अपने सनातन धर्म की गहराई का सही ज्ञान नहीं है।

पृष्ठ 01 का शेष...

बंगाल सरकार...

हालांकि, जरूरत पड़ने पर बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की भी छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा पर्याप्त ग्रेड-ए अधिकारियों को SIR प्रक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं कराने पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की मदद के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी तैनात रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मुख्य सचिव, डीजीपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों समेत सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाने का निर्देश। डीजीपी को SIR अधिकारियों को दी गई धमकियों पर क्या कदम उठाए गए, इस पर सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का आदेश। कोर्ट ने जो मामले अभी लंबित हैं, हाईकोर्ट प्रशासन उन्हें संभालने के लिए फिलहाल कोई अस्थायी व्यवस्था (अंतरिम व्यवस्था) बनाए। राज्य के जिला कलेक्टरों और एसपी को निर्देश दिया कि वे SIR कार्य के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को लॉजिस्टिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करें।

शाह मानहानि...

मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। कोर्ट से निकलने के बाद राहुल रामचेत मोची की दुकान पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। राहुल ने मोची की पोती श्रद्धा को गोद में लिया। उसके पैर में चोट देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। परिवार ने बताया कि चोट ठीक नहीं हो रही है। इस पर राहुल ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से बच्ची के इलाज की बात कही। उन्होंने बच्ची को चॉकलेट भी दी। रामचेत मोची की तीन महीने पहले कैंसर से मौत हो गई थी। डेढ़ साल पहले राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर बैठकर जूते सिले थे। बाद में उन्होंने रामचेत को सिलाई मशीन भी भेजी थी। शुक्रवार सुबह राहुल दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से कार से कोर्ट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। इसके चलते सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दूसरे गेट से बाहर निकाला। मामला 8 साल पुराना है। आरोप है कि राहुल ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने तब कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के वकील काशी शुक्ला को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह आखिरी मौका है, इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामचेत मोची सुल्तानपुर के रहने वाले थे। उनकी हाईवे के किनारे जूते-चप्पल सिलने की दुकान थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी इसी मामले में पेशी पर सुल्तानपुर आए थे।

अब अप्रैल से हर...

अभी इनको नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इसके साथ ही इनको भी पांच लाख रुपये कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस बार रानी लक्ष्मीबाई योजना से बेटियों को स्कूटी देने जा रहे हैं। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को लेकर भेदभाव होता था, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हमने पॉलिसी बना दी है। जो उस मानक को पूरा करेगा, उसे हम मान्यता देंगे। पहले छह कमिश्नरी ऐसी थीं, जिसमें कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अलीगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन, सहारनपुर,आजमगढ़ कमिश्नरी में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमने सभी जगहों पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के शासनकाल में शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट लगभग छह था। आज हम इसे 0-3 पर ले आए हैं। अब आठ हजार न्याय पंचायत तक कंपोजिट विद्यालय ले जाने का लक्ष्य है। पहले हर विधानसभा में एक-एक, फिर हर ब्लॉक में फिर हर न्याय पंचायत तक ले जाएंगे। जहां एक ही छत के नीचे 12वीं तक की पढ़ाई और कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शौचालय, पेयजल की व्यवस्था न होने से बच्चियां स्कूल छोड़ देती थीं। हमने हर स्कूल में इनकी सुविधा दी। जब हमने उसे पैसा देना चाहा तो उसने नहीं लिया। उसने बताया कि भाई है लेकिन वह निजी स्कूल में जाता है। इससे ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। फटा कुर्ता पहनकर, नंगे पैर, फटा बैग लेकर बच्चे स्कूल जा रहा था। जब हमने उसे पैसा देना चाहा तो उसने नहीं लिया। उसने बताया कि भाई है लेकिन वह निजी स्कूल में जाता है। ये कहानी सुनकर हमने प्रदेशभर में हर बेटी को दो जोड़ी ड्रेस, सूज, बैग देने की व्यवस्था की। बाद में हमने सभी बच्चों देने का काम शुरू किया।

गौरव गोगोई सही...

अगर वे दस साल बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देने कि बात पर रो रहे हैं, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के खिलाफ 20 पॉइंट्स की चार्जशीट जारी की। यह चार्जशीट असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार की गई है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रियंका गांधी असम की जनता की भावनाएं समझने आई हैं और कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

निजी अस्पतालों को देना होगा नर्स को न्यूनतम 20 हजार वेतन

स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिया आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सभी निजी अस्पतालों को अब अपने यहां नर्स को प्रति माह न्यूनतम 20 हजार रुपये वेतन देना होगा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सीएमओ को पत्र भेजकर इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कम वेतन देने वाले अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएमओ डॉ. एनवी सिंह का कहना है कि जिले के सभी निजी अस्पतालों को इस संबंध में ईमेल भेज दिया गया है। आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। राजधानी में एक हजार से अधिक छोटे-बड़े निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इसमें 10 से 50 बेड के करीब 84, जबकि 51 से 100 बेड तक के करीब 30 अस्पताल हैं। निजी अस्पतालों में नर्स को 10 से 12 हजार रुपये वेतन देकर 08 से 10 घंटे तक काम लिया जाता है। नर्सिंग स्टाफ को कम मानदेय या वेतन दिए जाने

का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि निजी अस्पतालों में नर्स को न्यूनतम 20 हजार रुपये वेतन दिलाने की व्यवस्था कराएं। कोर्ट के आदेश की कॉपी शासन के जरिये स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण के पास पहुंची तो उन्होंने सीएमओ लखनऊ को पत्र भेजकर इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के मुताबिक, 10 से 100 बेड तक के सभी निजी अस्पतालों को अब न्यूनतम 20 हजार रुपये वेतन नर्स को देना होगा। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676